माननीय सदस्यगण,

तेरहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है। आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और उम्मीद है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक विचार विमर्श प्रदेश के समग्र विकास और यहाँ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में चिन्तन की दृष्टि से उपयोगी और महत्त्वदायी रहेगा।

2. हमारे लिए गर्व का विषय है कि जयपुर में सात से नौ जनवरी तक दसवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन–2012 का ऐतिहासिक सफल आयोजन किया गया, जिसमें करीब साठ देशों के लगभग दो हजार प्रवासी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित हुए।

3. मातृभूमि से नई पीढ़ी को जोड़े रखने और उन्हें यहाँ की विरासत से रुबरु कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीयों के अठारह से अट्ठाईस आयु वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष अपने प्रदेश की यात्रा हेतु योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत उनकी हवाई यात्रा के किराये की नब्बे प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

4. मुझे खुशी है कि प्रदेश की जनता को बेहतर एवं पारदर्शी शासन देने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में नीतिगत निर्णय लेकर कई नवाचार लागू किए गए हैं, जिनसे आमजन का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

5. राज्य सरकार जनधन के समुचित सदुपयोग और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की अवधारणा के साथ सुशासन की स्थापना में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रियों की सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। इसी तरह राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं अन्य अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है।

6. प्रत्येक जिले का जिला प्रभारी बनाकर उन्हें जिले में चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रत्येक माह राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा है।

7. राज्य सरकार ने कई नई विकास नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें कृषि प्रसंस्करण एवं व्यवसाय प्रोत्साहन, पशुधन विकास, बायोमास आधारित परियोजना की स्थापना, राज्य पर्यावरण, वन, ईको–ट्यूरिज्म, जल, आवास, नवीन उद्योग एवं निवेश, टाउनशिप पॉलिसी, खनिज, वादकरण तथा सौर ऊर्जा के लिये नयी नीतियाँ जारी की गई हैं।

8. हमारी सरकार ने गाँव, गरीब और किसान की समृद्धि और खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य माना है। जिससे आमजन के जीवन स्तर में सुधार आया है।

माननीय सदस्यगण,

9. राज्य सरकार ने आमजन को खाद्य सुरक्षा, आवास सुविधा, चिकित्सा सेवा और निःशुल्क शिक्षा जैसी सेवाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'फ्लैगशिप कार्यक्रमों' की अभिनव शुरूआत की है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट एवं ''माँ'' जननी शिशु सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन से आम आदमी लाभान्वित हुआ है।

10. मुझे प्रसन्नता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवम्बर, 2011 से आम जनता को समयबद्धता के साथ लोक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में 15 विभागों की 124 सेवाओं में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को क्रियाशील कर दिया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जनता तक पहुँचाने के लिए जन–अभियोग निराकरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर 'ई–सुगम परियोजना' क्रियान्वित कर दी गई है। यह सेवा एकल खिड़की के साथ ही वेबसाईट के माध्यम से भी उपलब्ध है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञान संसाधन केन्द्रों के रूप में अब तक 245 पंचायत समितियों एवं 7 हजार 775 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है।

11. राज्य सरकार ने आमजन को बड़ी सौगात देते हुए, 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' प्रारम्भ की है। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इस योजना के तहत पन्द्रह हजार निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

12. राज्य में ग्रामीण बीपीएल परिवारों के स्वयं के आवासों की लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए 'इंदिरा आवास योजना' की तर्ज पर ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' लागू की गई है। इन दोनों कार्यक्रमों में तीन वर्षों में लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

13. ''मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना'' के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए हैं। एपीएल परिवारों को फोर्टीफाइड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति निगम का गठन किया जाकर इसके माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ यथा फोर्टीफाइड आटा, चाय, आयोडीनयुक्त नमक आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

14. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा राज्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हासिल करने में देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन तथा श्रेष्ठ वित्तीय मानकों को हासिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने पर राजस्थान की सराहना की है।

माननीय सदस्यगण,

15. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2010–11 के दौरान राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद, जहाँ 8.39 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, वहीं राज्य की वृद्धि दर 10.97 प्रतिशत रही है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर 6.35 प्रतिशत के मुकाबले राज्य में 9.39 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

16. राज्य के सतत् विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है तथा नव प्रवर्तन हेतु राज्य नव प्रवर्तन परिषद् का गठन भी किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लक्ष्य के सापेक्ष नब्बे प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित करने पर अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में रहा है।

17. आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, सड़कों के विकास और विस्तार, उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित सदुपयोग, जल संरक्षण एवं

पेयजलापूर्ति के साथ आर्थिक विकास के लिए कृषि विस्तार और औद्योगिक विकास की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इससे निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आकृष्ट हो रहे हैं और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

18. राज्य सरकार प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कृत संकल्प है। विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण तंत्र की सुदृढ़ता के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नये विद्युत गृह स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 11 हजार 590 मेगावाट क्षमता की 14 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। पहली बार छः सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं।

19. मुझे खुशी है कि बीते तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3 हजार 380 मेगावाट की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार विद्युतीकरण के कार्य को सर्वोपरि प्राथमिकता दे रही है।

20. राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के हब के रूप में विकसित हो रहा है। 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन' के तहत प्रथम चरण में पूरे देश में विकसित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की परियोजनाएँ स्थापित हो रही हैं।

21. बांसवाड़ा जिले में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति हेतु रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु राज्य सरकार इस परियोजना के लागत की 50 प्रतिशत राशि वहन करेगी। इस रेलवे लाईन का निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

22. राज्य में बीते तीन वर्षों में लगभग पाँच हजार किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों व जिला सड़कों तथा बीस हजार किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य किया गया है। मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों के गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए लगभग ढाई हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

23. उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिए पक्के खालों का निर्माण सिद्धमुख नोहर, अमरसिंह सब ब्रांच, गंग नहर परियोजना, चम्बल एवं बीसलपुर कमाण्ड नहरी क्षेत्रों में कराया जा रहा है तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बेहतर जल प्रबन्धन से इन्दिरा गांधी नहर के अन्तिम छोर, जो जैसलमेर जिले में हैं, तक किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

24. सेमली फाटक, कालीखर एवं दो नदी लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। नर्मदा नहर, गंगनहर आधुनिकीकरण एवं राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना तथा मध्यम परियोजनाओं में तकली, गागरिन, ल्हासी, पीपलाद, गरडदा एवं कई लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है । इसी तरह परवन बृहद् परियोजना, राजगढ़ एवं हथियादेह मध्यम परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट परियोजना के पाइलेट क्षेत्र व नर्मदा परियोजना में फव्वारा पद्धति के कार्य प्रगति पर हैं।

25. पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण हेतु राज्य सरकार ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार अधिक से अधिक सतही जल पर आधारित परियोजनाएँ स्वीकृत करने व भूजल पर आधारित पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाने की नीति अपनाई है। अब तक 29 बृहद् परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 28 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक बाहुल्य हैबिटेशन क्षेत्रों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में डीफ्लोरीडेशन यूनिट लगा कर शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। पुरानी व जर्जर पाईप लाईनों को बदल कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया है।

26. मुझे खुशी है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011' को पूरे राज्य में लागू करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रदेश में 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों हेतु यह अधिनियम एक अप्रैल, 2011 से लागू किया गया। अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपये का नया निवेश संभावित है।

27. राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना का चालीस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है। उसके विकास हेतु DMICDC के साथ अनुबन्ध किया गया है। DMIC परियोजना के प्रथम चरण में खुशखेड़ा– भिवाड़ी–नीमराना क्षेत्र में Investment Region को तथा द्वितीय चरण में जोधपुर–पाली–मारवाड़ को विकसित किया जा रहा है।

28. राजस्थान में जापानी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु देश का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र जापानी जोन के नाम से नीमराना में विकसित किया गया है। जहाँ 13 इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है एवं इससे 6 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज पर वित्तीय सहायता हेतु योजना तथा नई 'फ्लेक्सी ऋण योजना' प्रारम्भ की गई है। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन हेतु निःशक्तजनों को 15 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत एवं महिलाओं को 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत की रियायत दी गई है। राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित

बेरोजगार युवकों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिये कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" प्रारम्भ की है।

29. राज्य के छोटे एवं मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से पहली बार सभी शहरों के मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं।

30. जयपुर रीजन की वर्ष–2025 तक की भावी जनआवश्यकताओं तथा जयपुर को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किए जाने के मद्देनजर जयपुर के विकास की मास्टर योजना–2025 बनाकर 6 सितम्बर, 2011 से लागू की जा चुकी है। जयपुर में 'घाट की गूणी में सुरंग परियोजना' का कार्य, रामनिवास बाग में दो मंजिला पार्किंग परियोजना का कार्य एवं गुर्जर की थड़ी पर अन्डर पास का कार्य लगभग समाप्ति पर है । जिससे यातायात में भारी सुगमता आयेगी। पूरे प्रदेश में रेलवे के सहयोग से 32 रेलवे ओवर ब्रिज तथा अण्डरपास का कार्य प्रगति पर है ।

31. यातायात सुधार के लिए 'मैट्रो रेल परियोजना' की क्रियान्विति हेतु मानसरोवर से चाँदपोल तथा चाँदपोल से बड़ी चौपड़ तक का कार्य DMRC के माध्यम से करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में

अम्बाबाड़ी से सीतापुरा के सिविल कार्य, पटरी बिछाने एवं ओवरहैड ट्रेक्शन कार्य, रोलिंग स्टॉक, सिंगनलिंग, परिचालन एवं संधारण कार्य पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत किए जाने प्रक्रियाधीन हैं।

32. राज्य की कच्ची बस्तियों में सुधार एवं आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने की दृष्टि से इन बस्तियों में 15 अगस्त, 2009 तक बसे हुए परिवारों का सर्वे करवाया जा रहा है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि कच्ची बस्तियों में 300 वर्गगज तक के भूखण्डों का नियमितीकरण किया जाए और राजीव आवास योजना के तहत योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया जाए। जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख शहरों में आधारभूत विकास हेतु 49 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

33. खनिजों की उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है। मुझे खुशी है कि खनिज दोहन से राजस्व में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्षों में राज्य के जैसलमेर, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पूर्व परीक्षण द्वारा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के पर्याप्त भण्डार सिद्ध किए गए हैं। खनिज आयरन आधारित मूल्य संवर्धन संयंत्र तथा लिग्नाइट आधारित पॉवर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

34. राज्य में पेट्रोलियम सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति आर्थिक विकास की दृष्टि से शुभ संकेत है। बाड़मेर–सांचोर बेसिन, बीकानेर–नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन के अन्तर्गत 21 ब्लॉक अन्वेषण हेतु तथा 10 क्षेत्र दोहन एवं विकास हेतु आवंटित किए गए हैं। इसके साथ–साथ राज्य सरकार प्रदेश में रिफाईनरी की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्यगण,

35. मुझे खुशी है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2010–11 के लिए दलहनी फसलों के अधिकतम उत्पादन के फलस्वरूप राजस्थान राज्य को एक करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। देश में राजस्थान प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत करने वाला पहला राज्य है।

36. राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर नये बीज विधायन केन्द्र व गोदाम निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है।

37. सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निर्वाचित संचालक मण्डलों का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस वर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराए गए।

38. प्रदेश की विशाल एवं बहुमूल्य पशु सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने के लिए 'पशुधन विकास नीति' तैयार की गई है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था नहीं हैं, में प्रत्येक माह एक पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातक एवं पशुधन सहायकों को रोजगार के नवीन अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

39. मुझे खुशी है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में संस्थागत प्रशिक्षण देकर कुशल वाहन चालक तैयार करने हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से रेलमगरा जिला राजसमन्द में मोटर ड्राईविंग ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इसी परिसर में वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु आधुनिक कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस सेन्टर की स्थापना भी की जा रही है।

40. राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सभी संभाग मुख्यालयों पर ई–स्टेम्पिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

41. राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2011–2012 में कर निर्धारण प्रक्रिया को सरलीकृत किया है व डीम्ड कर निर्धारण सम्पूरित

किए जाकर व्यवसायियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर जिलों में पावरलूम सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित होने वाली नवीन इकाईयों द्वारा क्रय किए जाने वाले यार्न पर देय कर में 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

42. राज्य के सभी कोषालयों एवं उप कोषालयों में ऑनलाइन बिल पारित किए जा रहे हैं तथा राज्य की आय एवं व्यय की सूचना किसी भी समय ऑनलाइन देखी जा सकती है।

43. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृतियों एवं भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रणाली भी पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ कर दी गई है। इसके तहत ऑनलाइन वेतन बिल मॉड्यूल को मार्च, 2012 से राज्य के समस्त कोषालयों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

44. राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, स्थापत्य, किले, महल और देवालय देशी–विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकृष्ट करते हैं। राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। राज्य के उदयपुर को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल चयन होने पर राजस्थान को 'कोन्डे नास्ट ट्रेवलर अवार्ड' से नवाजा गया है। जन्तर–मन्तर को

यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया है। राज्य में ''एडवेंचर ट्यूरिज्म'' को बढ़ावा दिए जाने के लिए डेजर्ट सफारी, सिलिसेढ़ में वाटर स्पोर्ट्स, लाखेला तालाब–कुम्भलगढ़ में नौकायन तथा अन्तर्राष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन इकाई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन स्थानीय क्षेत्र की डी.एल.सी. दरों पर किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

45. मुझे खुशी है कि प्राचीन कला वैभव की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जन्तर मन्तर–जयपुर, फतेहगंज गुम्बद–अलवर, डीग किला–भरतपुर, बाला किला–अलवर, संग्रहालय आहड़–उदयपुर, संग्रहालय–जैसलमेर एवं अलबर्ट हाल–जयपुर के संरक्षण एवं विकास के कार्य करवाए गए हैं। डांग ट्युरिष्ट सर्किट योजनान्तर्गत चौबुर्जा किला, कुम्हेर महल, किशोरी महल भरतपुर में संरक्षण कार्य चालू है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में ऐतिहासिक व रेवेन्यू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन व

माइक्रोफिल्मिंग का कार्य हो चुका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में हस्तलिखित ग्रन्थों के डिजिटाईजेशन का कार्य चल रहा है।

46. राज्य में चिकित्सा सुविधा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि की गई है। ब्लड बैंकों के कम्प्यूटराईजेशन एवं ऑनलाईन करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती की जाकर पदस्थापन किए जा चुके हैं।

47. 'मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना' के अन्तर्गत राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, एचआईवी एड्स के मरीजों, वृद्ध, विधवा तथा विकलांग पेन्शनरों, नवजीवन योजना, अंत्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभान्वितों, कथौड़ी जनजाति, सहरिया एवं मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका के परिवारों को सम्पूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष से थैलेसीमिया एवं हिमोफीलिया के रोगियों को भी 2 अक्टूबर, 2011 से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा

रही है। साथ ही बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के निःसंतान दम्पत्तियों को यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च भी इस योजना के तहत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना से अब तक प्रदेश के लगभग एक करोड़ 3 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

48. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु 108 एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों की सभी पंचायत समितियों में 464 एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएँ दी जा रही हैं। राज्य के रेगिस्तानी एवं आदिवासी जिलों के दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सुविधा हेतु 'राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल सर्विस योजना' चलाई जा रही है। एनआरएचएम के अंतर्गत 104 चिकित्सा परामर्श सेवा प्रारम्भ की गई है। राज्य में गर्भवती महिला एवं शिशु टीकाकरण की ऑनलाईन ट्रेकिंग करने के लिए प्रसव पश्चात् हुए बच्चे के टीकाकरण की मॉनिटरिंग ऑनलाईन शुरू की गई है, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में 15 दिसम्बर, 2011 से हेपेटाईटिस–बी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की दीर्घगामी सुरक्षा के लिये यह एक अहम कदम है।

49. जयपुर में कार्यरत आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के कार्यालयों हेतु 'आयुष भवन' का निर्माण किया जा रहा है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद चिकित्सालय एवं छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है।

50. राज्य में बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए जहाँ राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं, वही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सभी गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण कार्य होता है, में कक्षा 1 अथवा प्री–स्कूल में कुल प्रविष्ट बालकों के 25 प्रतिशत ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी किया गया है।

51. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011–12 में कक्षा 10 के साथ–साथ कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। अब तक लगभग एक लाख 11 हजार साइकिलों

का वितरण हो चुका है। 'साक्षर भारत कार्यक्रम' 31 जिलों में लागू कर दिया गया है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स में से 91 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2011–12 से कक्षा 8, 10 एवं 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करवाया गया है और इसी के क्रम में वर्ष 2012–13 से कक्षा 6 व 7 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है।

52. राज्य में स्काउटिंग व गाइडिंग गतिविधियों का निजी विद्यालयों में भी विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर 'राष्ट्रीय आयुक्त' शील्ड से स्काउट संगठन को प्रथम एवं गाइड संगठन को द्वितीय स्थान घोषित कर सम्मानित किया गया है।

53. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2011–12 में 8 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स स्थापित किया गया है। किशनगढ़ में निजी सहभागिता के आधार पर महिला महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। 'देवनारायण योजना' के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ नादोती में राजकीय सह शिक्षा

महाविद्यालय एवं बयाना में महिला महाविद्यालय तथा महिला छात्रावास प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है । अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं, पीटीआई, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं अन्य कार्मिकों के कुल 1485 लोगों को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार निजी स्कूलों के 6 हजार 65 कार्मिकों को भी सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

54. मुझे खुशी है कि राज्य में प्रबन्धन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आई.आई.एम. का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में स्वयं का भवन निर्मित होने तक अस्थाई रूप में शुभारम्भ किया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आदिवासी क्षेत्र (सहरिया जाति) के लिए शाहबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा में एक पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए उदयपुर में एक पॉलीटेक्निक तथा बांसवाड़ा में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई.आई.आई.टी. संस्थान की स्थापना कोटा शहर में की जा रही है।

55. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना' के अन्तर्गत 5 हजार विज्ञान क्लबों की स्थापना की योजना है। जयपुर व झालावाड़ में विज्ञान पार्क स्थापित किए गए हैं। बॉयोगैस आधारित 'पॉवर जनरेटर फॉर रूरल एप्लीकेशन परियोजना' के अन्तर्गत बायोगैस एनरिचमेट प्लांट की जोधपुर में स्थापना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में 300 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। 51 स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

56. मुझे प्रसन्नता है कि मिड–डे–मील कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों एवं शिक्षा गारन्टी केन्द्रों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए कुक कम हेल्पर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों में ज्यादातर महिलाएँ है, जिन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है।

57. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना संचालित की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु व सीमांत काश्तकारों को स्वयं के खेत पर कार्य कराने के लिए 'अपना खेत, अपना काम' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

58. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्रामस्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण विकास की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ और अधिकार सम्पन्न बनाकर सक्रिय किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए आम जनता से जुड़े पाँच विभागों को प्रभावी रूप से हस्तान्तरण के लिए राज्य को प्रथम पुरस्कार के रुप में प्रशस्ति–पत्र एवं डेढ़ करोड़ की राशि प्रदान की गई है। पंचायत समितियों में रिक्त कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पंचायतों को इस वर्ष एक हजार करोड़ रुपये की राशि हस्तान्तरित की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार सम्पन्न

बनाने हेतु पीसा (PESAA) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम–2011 अनुसूचित किए गए हैं।

59. राज्य में कस्टोडियन भूमि की खातेदारी की समस्या बहुत लम्बे समय से चली आ रही थी। अतः राज्य सरकार द्वारा कस्टोडियन कृषि भूमि के पूर्व आंवटियों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम में संशोधन कर बाजार कीमत की 25 प्रतिशत के बजाय नाम मात्र की राशि निर्धारित कर काश्तकारों को राहत प्रदान की गई है। काश्तकारों को अपने खेत में जाने के लिए कानून में संशोधन करके रास्तों का प्रावधान किया गया है ।

60. प्रदेश में राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण (NLRMP) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्र परिवर्तित योजना मद में मैप डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है, इसके तहत टोंक जिले की समस्त तहसीलों के नक्शों को डिजिटाईड करने का कार्य NIC द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

61. राजस्थान के पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों को संविदा के आधार पर नियोजन दिलवाने, उन्हें स्वावलम्बी

बनाने एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम होगा।

62. प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि राजस्थान की क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार 'रणजी ट्रॉफी' में चैम्पियन बनकर प्रदेश की समृद्ध खेल परम्पराओं में एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं अपनी ओर से एवं आप सबकी ओर से विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम प्रबंधकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा इस उपलब्धि के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम को इस वर्ष एक करोड़ 11 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

63. राज्य सरकार प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रुप से आधारभूत खेल सुविधाएँ विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने राष्ट्रमण्डल व एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान एवं पुरस्कार का सिलसिला प्रारम्भ किया है। जोधपुर में मल्टीपरपज इण्डोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। राज्य के छः स्थानों पर डे–बोर्डिंग कोचिंग स्कीम, एस.एम.एस. स्टेडियम में फिटनेस सेन्टर के साथ ही

झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर Physical Education and Sports University व भरतपुर में खेल संकुल की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देते हुए 'राजीव गांधी यूथ क्लब' का गठन किया जा रहा है।

64. घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर पर 25 रुपये प्रति सिलेण्डर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष 125 करोड़ रुपये का व्यय भार राज्य सरकार वहन कर रही है। सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 54 पैसे की रियायत दी है, जिससे उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपये की राहत मिल रही है।

65. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार कर कमजोर, पिछड़े, गरीब और अशक्त लोगों को सुरक्षा कवच के दायरे में लाया गया है, जिससे इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय एक हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में पहली बार 'विशेष योग्यजन निदेशालय' की स्थापना की जा रही है

तथा निःशक्तजन नीति शीघ्र लागू की जाएगी। निःशक्तजनों के राजकीय सेवाओं में आरक्षण हेतु राजस्थान निःशक्त व्यक्ति नियम–2011 लागू किए जा चुके हैं।

66. 'पालनहार योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष सहायता उपलब्ध कराकर 47 हजार से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है। 'अनुप्रति योजना' के अन्तर्गत लगभग 400 अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु सहायता राशि 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये की गई है। 'महाराणा प्रताप मकान निर्माण सहायता योजना' में गाड़िया लोहारों को दी जाने वाली सहायता 35 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये की गई है।

67. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से राज्य में दो लाख बीस हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और इन समूहों को प्राथमिकता से वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिए जा रहे हैं और ऋण पर देय ब्याज की पचास प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य राजकीय

अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को 'कलेवा योजना' के अंतर्गत तीन दिन निःशुल्क गरम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

68. राज्य में स्थापित नये अल्पसंख्यक विभाग ने अपने पहले वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय शुरू किए गए हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भारी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार की नई मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। जयपुर, कोटा एवं अजमेर में कन्या छात्रावास आरम्भ किए गए हैं। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अल्पसंख्यक युवकों एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए 'अनुप्रति योजना' भी लागू की गई है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के 10 स्थानों पर राजकीय आई.टी.आई. स्थापित कर जुलाई, 2011 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

69. श्रम कल्याण के लिए राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों

जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी निर्माण व नरेगा श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा दुर्घटना पर तत्काल सहायता योजना, समूह बीमा योजना, महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना, हिताधिकारी की पुत्री एवं स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

70. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अलवर जिले में खनन एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अलवर जिले का पर्यावरणीय मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है।

71. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत 'राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व' की स्थापना हेतु मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है । वन्य जीवों एवं वन सम्पदा के संरक्षण हेतु लगभग 508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को "कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान" घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में युवकों को समिति के माध्यम से "वन मित्र" के रूप में मानदेय पर लगाया जा रहा है।

72. राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक एवं पुण्यार्थ गठित प्रन्यासों के माध्यम से लोक सरोकारों की नई संस्कृति विकसित करने हेतु कृत संकल्प है। गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुरूप शिक्षा, चिकित्सा व विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु लोक प्रन्यासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । श्रीनाथद्वारा मन्दिर मण्डल व सांवलिया जी मन्दिर मण्डल द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर श्री तेजाजी–नागौर में नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

73. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 155 नये पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों को 'मेडिक्लेम और दुर्घटना समूह बीमा योजना' उपलब्ध कराने के लिए भी योजना लागू की है।

74. न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलम्ब को कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जोधपुर शहर को महानगर घोषित होने के फलस्वरूप जोधपुर में एक जिला न्यायालय, एक सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड न्यायालय तथा जयपुर में दो सी.बी.आई. न्यायालयों की स्थापना की गई है।

जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के नये भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। वादकरण के प्रभावी प्रबंधन हेतु स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2011 बनाई गई है।

75. राज्य में वर्ष 2011 के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2011–2012 में पुलिस बल हेतु उपकरण, वाहन, हथियारों एवं निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीय अंशदान के रूप में भारत सरकार द्वारा 52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु 24 जिलों में प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। इसके लिये राज्य के 17 जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन भी किया गया है।

76. माननीय सदस्यगण इस सत्र में कई विधेयकों के साथ–साथ निम्न वित्तीय एवं विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के प्रति स्थापक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे :–

1. वर्ष 2012–13 के लिये आय–व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य।
2. वर्ष 2011–12 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित कार्य।

77. हमारी सरकार आम आदमी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए संकल्पवान होकर कार्य कर रही है। बेहतर और पारदर्शी शासन के साथ सुशासन की स्थापना की दिशा में कई नवाचारों के साथ निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। अपने वायदे के अनुरुप हमारी सरकार नये राजस्थान के नव–निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध है, इस दिशा में अब तक किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

78. शासन में पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र रुपी रथ के दो पहिए हैं। इन दोनों पहियों के निरन्तर गतिशील रहने से ही लोकतंत्र प्राणवान और गतिवान बनता है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का समान उद्‌देश्य है। आप सभी प्रदेश के समग्र विकास, समृद्धि और खुशहाली के साथ आमजन की गरिमा को बढ़ाने के लिए निरन्तर चिन्तन–मनन में अभिरुचि रखने के पक्षधर हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के हित चिन्तन के लिए किए जाने वाला सामूहिक विचार–विमर्श प्रदेश की नीतियों और कार्यक्रमों को लोकहित में और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन में उपयोगी और महत्त्वदायी सिद्ध होगा।

माननीय सदस्यगण,

79. अंत में मैं ऋग्वेद की ऋचा के भावों में आपके प्रति यह शुभ कामना व्यक्त करता हूँ –

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

आप सबके संकल्प समान हों, आप सबके हृदयों की धड़कन समान प्रेरणा से जुड़ी हों । अतः इस कार्य में आपके मानस समान रूप से हित चिंतन करें, जिससे जनहित में आप सबका सहकार मिल सके।

जय हिन्द !